



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 2018/कार्तिक 7, 1940

No. 347]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 2018/KARTIKA 7, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2018

मामला सं – एसएसआर 17/2018

विषय – चीन जन. गण., थाइलैंड और यूएसए से पीवीसी सम्पेशन ग्रेड रेजिन के आयातों के संबंध में निर्णयिक समीक्षा जांच की शुरूआत

फा. सं. 7/34/2018-डीजीटीआर.—1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने 26 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं 14/08/2006-डीजीएडी द्वारा ईयू, ताइवान, चीन जन. गण., जापान, थाइलैंड और यूएसए (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पालीविनाइल क्लोरोराइड सम्पेशन रेजिन (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

2. यतः ताइवान, चीन जन गण, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड, यूएसए और कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंध मूल जांच प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई थी और तत्पश्चात 26 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना सं 14/08/2006-डीजीएडी द्वारा प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अधिसूचना सं 11/2008 के माध्यम से 23 जनवरी, 2008 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। अंतिम जांच परिणाम के जारी होने के बाद, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं 14/8/2006-डीजीएडी के माध्यम से दिनांक 14 फरवरी, 2018 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया जिसके जरिए शुल्क तालिका में संशोधन किया गया और उसे 24 मार्च, 2008 अधिसूचना सं 38/2008 के जरिए सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा तदनुसार लगाया गया था। इस आदेश से व्यथित होकर हितबद्ध पक्षों ने सेस्टेट की शरण ली और मामला वापस प्राधिकारी के पास भेजा गया। जांच के बाद, प्राधिकारी ने 26 दिसम्बर, 2007 को प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की पुनःपुष्टि की। तत्पश्चात एक समीक्षा जांच की गई और प्राधिकारी ने कोरिया को छोड़कर 6398 GI/2018

संबद्ध देशों पर शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13 जून, 2014 की अधिसूचना सं 27/2014 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाया।

3. यतः, मूल जांच 5 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. 14/1012/2012-डीजीएडी के जरिए ईयू और मैक्सिसको से संबद्धस्तु के आयातों के विरुद्ध शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 4 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं 14/1012/2012-डीजीएडी के जरिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13 जून, 2014 की अधिसूचना सं 26/2014 द्वारा ईयू और मैक्सिसको से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाया।

4. यतः मै. डीसीडब्लू लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और मै. कैमप्लास्ट सनमर लि. ने मौजूदा एडीडी के समाप्त होने पर पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए अधिनियम और नियमों के अनुसार ईयू, मैक्सिसको, ताइवान, चीन जन गण., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड और यूएसए से आयातों पर एडीडी की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक संयुक्त आवेदन दायर किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

5. पूर्ववर्ती जांचों तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ‘विनाइल क्लोराइट मोनोमर के होमो-पालीमर (स्पैंशन ग्रेड)’, जहां विभिन्न पालीमर शृंखला एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, जो सीमाशुल्क वर्गीकरण सं 3904 के अधीन आते हैं। विचाराधीन उत्पाद में विशेष पीवीसी स्पैंशन रेजिन जैसे क्रास लिंकड पीवीसी, क्लोरिनेटेड पीवीसी(सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइट – विनाइल एसिटेट कोपालिमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेजिन और पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन शामिल नहीं हैं। विचाराधीन उत्पाद को वर्तमान अधिसूचना में ‘पानी विनाइल क्लोराइट (पीवीसी) रेजिन’, ‘स्पैंशन ग्रेड’ या ‘पीवीसी स्पैंशन रेजिन’ या ‘संबद्ध वस्तु’ के रूप में बताया गया है।

6. वर्तमान जांच की शुरूआत मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा जाँच है और चूंकि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पूर्ववर्ती जांचों के बाद से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच के समान ही रहेगा।

ख. समान वस्तु

7. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा जाँच है इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती जांच में यह पहले निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

8. वर्तमान याचिका मै. डीसीडब्लू लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और मै. कैमप्लास्ट सनमर लि. द्वारा दायर की गई है जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। याचिकाकर्ताओं के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तु के दो अन्य उत्पादक हैं अर्थात रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

9. याचिकाकर्ता कंपनियों ने प्रमाणित किया है कि डीसीएम श्रीराम लि. को छोड़कर उनमें से किसी ने भी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। डीसीएम श्रीराम लि. के संयुक्त उद्यम श्रीराम एक्सिआल प्रा. लि. ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। यह नोट किया जाता है कि श्रीराम एक्सिआल प्रा. लि. द्वारा किए गए आयात भारत में उत्पाद के आया, भारतीय उत्पादन और डीसीएम श्रीराम लि. की खपत और उत्पादन के संबंध में काफी कम है। प्राधिकारी ने विचार किया है कि इन आयातों से डीसीएम श्रीराम लि. नियमावली के अधीन घरेलू उद्योग का अपात्र नहीं हो जाता है। तथापि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय इस पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

10. याचिकाकर्ता कंपनियों का मिलकर भारतीय उत्पादन में 30.14 प्रतिशत हिस्सा है और इसलिए वे भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखती हैं। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ब) के भीतर याचिकाकर्ता कंपनियों को घरेलू उद्योग माना है।

घ. निर्णायिक समीक्षा की शुरूआत

11. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्षात्कृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जाँच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को

हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।

इ. शामिल देश

12. पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और उसकी अवधि बढ़ाने संबंधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध करने की याचिका ईयू, मैक्सिको, ताइवान, चीन जन गण., इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, थाइलैंड और यूएसए से आयातों के संबंध में दायर की गई है। याचिका और पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना के संबंध में उसमें दिए गए साध्यों के विश्लेषण के बाद, प्राधिकारी मानते हैं कि ईयू, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान और मलेशिया से आयातों के संबंध में समीक्षा जांच की शुरूआत करने का अपर्याप्त औचित्य है। वर्तमान समीक्षा जांच के दायरे को इसलिए केवल चीन जन. गण., थाइलैंड और यूएसए से विचाराधीन उत्पाद के आयातों तक सीमित कर दिया गया है।

ज. जांच अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक की है। क्षति जांच अवधि के रूप में 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 और जांच अवधि पर विचार किया गया है।

छ. प्रक्रिया

14. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 4 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना सं 21/29/2011-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे जिसमें चीन जन. गण., थाइलैंड और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी सस्पेंशन ग्रेड रेजिन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी।

ज. प्रक्रिया और सूचना प्रस्तुत करना

15. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातिकों, उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निम्नलिखित को प्रस्तुत करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार निदेशालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

16. संबंधित नियमावली के नियम 6(5) और 6(6) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिकी उत्पादकों और उपभोक्ता संगठनों को भी पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

झ. समय-सीमा

17. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार जिसका पता उपलब्ध नहीं है, भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

ञ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

18. नियमावली के नियम 8 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

19. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निभर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ट. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

24. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साध्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ठ. प्रतिदर्श

25. इस कार्यवाही में संबद्ध देशों में बड़ी संख्या में नियांत्रिक (कों)/उत्पादक (कों) द्वारा भागीदारी की संभावना और जांच पूरी करने की सीमित समयावधि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच किए जाने वाले नियांत्रिक (नियांत्रिकों)/उत्पादक(उत्पादकों) को प्रतिदर्श का चयन करके तर्कसंगत संख्या तक सीमित कर सकते हैं। नियमावली की नियम 17(3) के अनुसार, यदि अपेक्षित होगा, तो प्रतिदर्श लिया जाएगा।

ढ. असहयोग

26. नियम 6(8) के अनुसार, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक वाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2018

Case No. SSR 17/2018

Sub: - Initiation of Sunset Review investigation concerning imports of PVC Suspension Grade Resin from China PR, Thailand and USA.

File No.7/34/2018-DGTR.—(1) Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “Polyvinyl Chloride Suspension Resin” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from

EU, Taiwan, China PR, Japan, Thailand and USA (hereinafter referred to as the subject countries) through notification No. 14/08/2006-DGAD on 26th December, 2007.

2. WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand, USA and Korea RP was initiated by the Authority and thereafter Final Finding Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/8/2006-DGAD dated 26th December, 2007 recommending imposition of definitive duty. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed with w.e.f 23rd January, 2008 through Notification No. 11/2008. Post issuance of the final finding, the Authority issued a corrigendum was issued dated 14th February, 2018 through Notification No. 14/8/2006-DGAD making modification in the duty table and the same was imposed accordingly by the Customs Authorities through Notification no. 38/2008 dated 24th March, 2008. Aggrieved by the order; interested parties approached the CESTAT and the matter was remanded back to the Authority. Post investigation, the Authority reaffirmed the decision passed by the Authority on 26th December, 2007. A review investigation was carried on thereafter and the Authority recommended continued imposition of duty on the subject countries excluding Korea. The Ministry of Finance extended definitive anti-dumping duty vide notification No. 27/2014 dated 13th June, 2014.
3. WHEREAS, an original investigation was initiated against the import of subject goods from EU and Mexico through Notification No. 14/1012/2012-DGAD dated 5th October, 2012. The Authority recommended imposition of definitive anti-dumping duty through notification No. 14/1012/2012-DGAD, dated 4th April, 2014. Ministry of Finance imposed definitive anti-dumping duties on imports of subject goods from EU and Mexico through Notification No. 26/2014, dated 13th June, 2014.
4. WHEREAS, M/s DCW Limited, DCM Shriram Limited and M/s Chemplast Sanmar Limited have filed a combined application seeking extension of ADD on imports from EU, Mexico, Taiwan, China PR, Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and USA, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of existing ADD.

A. Product Under Consideration

5. The product under consideration in the previous investigations as well as present investigation is “*homopolymer of vinyl chloride monomer (suspension grade), where various polymer chains are not linked to each other, falling under Customs Classification No. 3904*”. The product under consideration excludes specialty PVC suspension resins such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin and PVC blending resin. The product under consideration has been referred to as “Poly Vinyl Chloride (PVC) Resin”, “Suspension Grade” or “PVC Suspension Resin” or “the subject goods” in the present notification.
6. The present initiation is for sunset review investigations of existing anti-dumping duty and as there are no known major developments since the previous investigations with regard to product under consideration, the scope of the product under consideration is the same as that of original investigation.

B. Like Article

7. Petitioners have claimed that there is no known difference in the product produced by the petitioners and exported from the subject countries. Subject goods produced by the domestic industry are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods with the subject goods imported from the subject countries. The consumers are using the two interchangeably. The current investigation being a sunset review investigation, the Designated Authority earlier determined in the previous investigations that the goods produced by the domestic industry is like article to the imported product.

C. Domestic Industry and Standing

8. The present petition has been filed by M/s DCW Limited, M/s DCM Shriram Ltd. and M/s Chemplast Sanmar Limited whose production constitutes a major proportion in the Indian production. Apart from the petitioners, there are two other producers of the subject goods in India namely Reliance Industries Limited and Finolex Industries Limited.

9. The petitioning companies have certified that none of them has imported the subject goods from the subject countries with the exception of DCM Shriram Limited. DCM Shriram Limited's joint venture namely Shriram Axiall Private Limited has imported the subject goods. It is noted that the imports made by Shriram Axiall Private Limited are quite insignificant in relation to imports of the product in India, Indian production & consumption and production of DCM Shriram Limited. The Authority has considered that these imports do not render DCM Shriram Ltd. as ineligible domestic industry under the Rules. However, these would be appropriately considered while evaluating impact of dumped imports on the domestic industry.
10. The petitioning companies together constitute 30.14% of the Indian production and therefore constitute a major proportion in the Indian production. The Authority has considered the petitioner companies as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

D. Initiation Of Sunset Review Investigation

11. In view of the duly substantiated application filed by the petitioners and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates the investigation to review the need for continued imposition of duties in force in respect of the subject goods, originating in and or exported from subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

E. Countries Involved

12. The petition has been filed seeking initiation of review investigations and extension of ADD in respect of imports from EU, Mexico, Indonesia, Taiwan, Japan, Malaysia, China PR, Thailand and USA. After analysis of the petition and evidences therein with regard to likelihood of the continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority considers that there is insufficient justification for conducting review investigations in respect of imports from EU, Mexico, Indonesia, Taiwan, Japan and Malaysia. The scope of the present review investigation is therefore restricted to imports of the product under consideration from China PR, Thailand and USA only.

F. Period Of Investigation

13. The period of investigation for the purpose of present investigations is April, 2017 to March, 2018. The injury investigation period has been considered as the period 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the period of investigation.

G. Procedure

14. The present sunset review covers all aspects of the final findings published vide Notification No. 21/29/2011-DGAD dated 4th April, 2014 recommending imposition of anti-dumping duty on imports of PVC Suspension Grade Resin originating and exported from China PR, Thailand and USA.

H. Procedure & Submission of information

15. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassies, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being informed separately to enable them to submit all information relevant in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

16. As per Rule 6(5) and 6(6) of the Rules supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the product under investigation, and consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causal link. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limits set out below.

I. Time limit

17. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/information within 40 days from the date of publication of this notification.

J. Submission of Information on Non-Confidential basis

18. In terms of Rule 8 of the Rules, the interested parties are required to submit non- confidential version of any confidential information provided to the Authority. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.
19. Information supplied without any mark as "Confidential" shall be treated as non- confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.
20. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
21. The non- confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
22. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
23. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

K. Inspection of Public File

24. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

L. Sampling

25. In view of the possibility of participation by large number of exporter(s)/producer(s) in the subject countries involved in this proceeding and the limited time period for completion of the investigation, the Authority may limit the exporter(s)/producer(s) to be investigated to a reasonable number by selecting a sample. The sampling shall be carried out, if required, in terms of Rule 17(3) of the Rules.

M. Non cooperation

26. In terms of Rule 6(8), in case where an interested party refuses access to or does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General